भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **798**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डाईमोनियम फास्फेट उर्वरक का आयात

798. श्री अरुण गोविल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पन्द्रह लाख टन डाईमोनियम फास्फेट उर्वरक का अपर्याप्त आयात किए जाने के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और
(ख) रबी के मौसम के दौरान महत्वपूर्ण उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। एनबीएस नीति के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख): किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। 2024-25 में, सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए ₹2625 करोड़ के अनुमानित वित्तीय निहितार्थ के साथ पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है ।

****